

- वर्ष 2020-21 के बजट में 30,42,230 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। यह 2019-20 के संशोधित अनुमानों से कितना प्रतिशत अधिक है? - **मात्र 12.7%**
- वर्ष 2020-21 में कुल व्यय में से राजस्व व्यय के 26,30,145 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? - **मात्र 11.9%**
- कुल व्यय में से सबसे ज्यादा हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा करों और शुल्कों में से राज्यों को दी जाने वाली राशि का होता है। वर्ष 2020-21 में इस मद में कितने प्रतिशत का व्यय अनुमानित है? - **20 प्रतिशत**
- इसके बाद 18 प्रतिशत हिस्सा व्याज की अदायगी में चला जाता है। रक्षा सेवाओं पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? - **मात्र 8%**
- 2020-21 में 10,96,520 करोड़ रुपये का कुल अप्रत्यक्ष कर जमा होने का अनुमान है। इसमें से सरकार को जीएसटी से 6,90,500 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। जीएसटी के अंतर्गत जमा किए गए कुल करों में से कितना प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी का हिस्सा है? - **84% (5,80,000 करोड़ रुपये)**
- वर्ष 2020-21 का विनिवेश लक्ष्य 2,10,000 करोड़ रुपये है। यह लक्ष्य 2019-20 के संशोधित अनुमान से कितना प्रतिशत अधिक है? - **कुल 223.1 प्रतिशत**
- जिन 13 मंत्रालयों को सबसे अधिक आवंटन किया गया है, उनमें संचार मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय शामिल हैं। इनके आवंटनों में सबसे अधिक बढ़ोतरी किस मंत्रालय के लिए दर्ज की गई है? - **संचार मंत्रालय (129%)**
- वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% है, जोकि 2019-20 के 3.8% के संशोधित अनुमान से कम है। वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित राजस्व घाटा कितना है? - **जीडीपी का 2.7%**
- प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और व्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है। 2020-21 के लिए अनुमानित प्राथमिक घाटा कितना अनुमानित है? - **जीडीपी का 0.4%**
- बजट अनुमान के मुताबिक सरकार की कुल बकाया देनदारियां 2000-01 में जीडीपी के 55.5% से गिरकर 2020-21 में 50.1% हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि एफआरबीएम एक्ट ऋण-जीडीपी अनुपात को किस वर्ष तक 40% करने का लक्ष्य रखा है? - **वर्ष 2024-25 तक**
- वर्ष 2020-21 में सब्सिडी पर कुल खर्च घटकर 2,62,109 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में खाद्य सब्सिडी के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? - **1,15,570 करोड़ रुपये**
- वर्ष 2020-21 के बजट में 2.5 लाख (कोई कर नहीं) और 2.5 से 5 लाख (5% कर) तक की आमदनी पर कोई नया कर प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है, लेकिन 5 से 7.5 लाख रुपये तक की वार्षिक व्यक्तिगत आय पर कर का प्रतिशत 20 से कम करके कितना कर दिया है? - **मात्र 10 प्रतिशत**
- वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में प्रत्यक्ष कर भुगतानों में मुकदमेवाजी को कम करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गयी है? - **'विवाद से विश्वास' योजना**
- भारतीय शेयर बाजार को अब और भी अधिक आकर्षक बनाने, निवेशकों के एक बड़े वर्ग को राहत देने और निवेश के लिए भारत को एक आकर्षक देश बनाने के लिए केंद्रीय बजट में किस कर को हटाने का प्रस्ताव किया गया है? - **लाभांश वितरण कर (डीडीटी)**

आपदा सक्षम अवसंरचना गठबंधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्ययोजना शिखर सम्मेलन, 2019 में आपदा सक्षम अवसंरचना गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure : CDRI) की स्थापना की घोषणा की। इसका सचिवालय नयी दिल्ली में स्थित है। इस वैश्विक भागीदारी से अनेक सतत विकास लक्ष्यों के साथ-साथ सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे आपदा सक्षम अवसंरचना पर फोकस करते हुए जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाना आसान होगा। इसमें विभिन्न देशों की सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, वित्तीय व्यवस्थाओं, निजी क्षेत्र और ज्ञान संस्थानों की भागीदारी होगी। इस गठबंधन को 35 से अधिक देशों के परामर्श से विकसित किया गया है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज

सेबी के नियमों के तहत सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाएगा। इसके जरिए सामाजिक कार्य से जुड़े एनजीओ शेयर मार्केट में सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां से पूंजी जुटाया जाएगा। इस प्रकार के एक्सचेंज यूके और कनाडा में पहले से ही काम कर रहे हैं।

स्मृति योजना

सरकार ने 'पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना (स्मृति)' के तहत और ज्यादा साझा सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। इससे पारंपरिक उद्योगों को और ज्यादा उत्पादक, लाभप्रद एवं सतत रोजगार अवसरों को सृजित करने में सक्षम बनाने के लिए क्लस्टर आधारित विकास को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। इसके

केंद्रीय बजट 2020-21

- प्राथमिकता वाले सेक्टरों में विदेशी सरकारों के सॉवरन वेलथ फंड के निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में 31 मार्च, 2024 से पहले अवसंरचना एवं अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में किये गये निवेश पर प्राप्त पूंजीगत लाभ आय, व्याज एवं लाभांश पर कितनी छूट देने का प्रस्ताव किया गया है? - **शत-प्रतिशत**
- वर्ष 2020-21 के बजट में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, चांगवानी, अनाज भंडारण, पशुपालन और नीली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर केन्द्रित किस कार्ययोजना की घोषणा की गयी है? - **16 मूत्री कार्ययोजना**
- नीली अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है? - **200 लाख टन**
- सरकार ने सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2020-21 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितनी राशि दी गयी है? - **6,400 करोड़ रुपये**
- 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' अभियान के जरिये कब तक देश से तपेदिक उन्मूलन की दिशा में सशक्त प्रयासों का प्रस्ताव किया गया है? - **वर्ष 2025 तक**
- 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के कारण शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात लड़कों से अधिक हुआ है। प्राथमिक स्तर पर लड़कों का नामांकन अनुपात 89.28% है। लड़कियों का नामांकन अनुपात कितना है? - **94.32 प्रतिशत**
- अधिक निर्यात ऋण के वितरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक कौन-सी नई योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत मुख्यतः छोटे निर्यातकों को आवश्यक सहयोग दिया जाएगा? - **निर्विक योजना**

तहत फोकस वाले क्षेत्र या सेक्टर बांस, शहद और खादी क्लस्टर हैं। 'स्कूर्ति' के तहत वर्ष 2019-20 के दौरान 100 नए क्लस्टर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिससे 50,000 कारीगर आर्थिक मूल्य शृंखला से जुड़ सकेंगे।

जीरो बजट खेती

आम बजट में जीरो बजट खेती को बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई है। इस प्रकार की खेती में पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर पारंपरिक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा। इसमें कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और हाइब्रिड बीज जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

नारी नू नारायणी

इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जायेगी। साथ ही, महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जायेगी।

हर घर जल

देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाये गए जल शक्ति मंत्रालय के लिए 2024 तक हर घर जल (पाइपलाइन से जल की आपूर्ति) का लक्ष्य तय किया गया है। उक्त मंत्रालय के लिए 28261 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें जल संसाधन, नदी संरक्षण और गंगा संरक्षण विभाग के लिए 8245 करोड़ रुपये तथा पेयजल स्वच्छता विभाग के लिए 20016 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मंत्रालय 2024 तक राज्यों के साथ मिलकर जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल उपलब्ध करायेंगा। जल जीवन मिशन पेयजल व स्वच्छता विभाग के तहत स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन की समेकित मांग और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें वर्षा जल संचय, भूमि जल संभरण और परिवारों के अवशिष्ट जल का कृषि के लिए फिर से प्रयोग जैसे साधनों को बनाये रखने के लिए स्थानीय अवसंरचना का निर्माण करेगा।



- 1480 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ 4 वर्षों की कार्यान्वयन अवधि वाला कौन-सा मिशन शुरू किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्तुओं के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है?

- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के अंतर्गत छोटे खुदरा विक्रेता, व्यापारी, दुकानदार आदि आते हैं। इन उद्यमों के लिए टर्नओवर की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?

- 5 करोड़ रुपये

- कम नगद वाली (Less Cash) अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह बढ़ाई गई सीमा केवल उन्हीं उद्यमों पर लागू होगी, जिनके कारोबार में नगद लेनदेन की हिस्सेदारी कितनी है?

- 5% से कम

- अगले 5 वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके मद्देनजर 31 दिसम्बर, 2019 को 103 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली किस परियोजना का शुभारंभ किया गया?

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन प्रोजेक्ट

- वर्ष 2020-21 के रेल बजट में कितनी राशि का आधिक्य बताया गया है?

- 6500 करोड़ रुपये

- वर्ष 2020-21 में रेलवे की 2,08,000 करोड़ की कुल आय का अनुमान लगाया गया है। इसमें से माल टुलाई से होने वाली आय कितनी है?

- 1,47,000 करोड़ रुपये

- वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में कुल रक्षा आवंटन 4,71,378 करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष से कितना ज्यादा है?

- मात्र 9.37%

- वर्ष 2020-21 का कुल रक्षा बजट, केंद्र सरकार के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है?

- मात्र 15.49%

- जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को जमा राशि बीमा का दायर, जो इस समय 1 लाख रुपये है, उसे बढ़ाकर प्रति जमाकर्ता कितना करने की अनुमति प्रदान की गई है?

- 5 लाख रुपये

- संग्रहालय विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान की विधाओं में अच्छी तरह प्रशिक्षित संसाधनों के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत पहली बार किस संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसे मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा होगा?

- भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान

- बजट 2020-21 में रांची (झारखण्ड) में जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा कहाँ पर एक पोत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जो हड़प्पा युग का एक नौवहन स्थल भी है?

- लोथल, अहमदाबाद

- बजट में अराजपत्रित पदों की भर्ती हेतु एक कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा के संचालन के लिए किस नाम से एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन की स्थापना की घोषणा की गयी है?

- राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए)

- क्वांटम प्रौद्योगिकी कम्प्यूटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा के साथ-साथ व्यापक स्तर के अनुप्रयोगों में नये मार्ग खोल रही है। इसके लिए किस मिशन में 5 वर्षों की अवधि के दौरान 8,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है?

- राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग मिशन

- नवगठित संघशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के चतुर्दिक विकास के लिए वर्ष 2020-21 के बजट में 30,757 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से लद्दाख के लिए कितनी राशि दी गयी है?

- 5,958 करोड़ रुपये

- वर्ष 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन तक पहुँच जाने की परिकल्पना की गई है। इसके लिए भारत को प्रति वर्ष औसतन कितने रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी?

- 20 लाख करोड़ रुपये

जल शक्ति अभियान

केंद्र सरकार ने भूजल को लेकर गंभीर स्थिति में पहुँचे 256 जिलों के 1592 ब्लॉकों की पहचान की गई है। इसके लिए जल शक्ति अभियान भी शुरू किया गया है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध धन का इस्तेमाल करने के अलावा सरकार पूरक वित्तिकी निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के तहत उपलब्ध अतिरिक्त धन के इस्तेमाल की संभावना भी तलाशेगी। इन योजनाओं के जरिए इन जगहों की स्थिति को सुधारा जाएगा।

पेमेंट बैंक

भारतीय मौद्रिक नीति का मुख्य नियंत्रक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 अगस्त, 2015 को भारती एयरटेल, डाक विभाग और विदेशी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी वांडाफोन सहित कुल 11 कंपनियों को पेमेंट बैंक (भुगतान बैंक) सेवा शुरू करने को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी। पेमेंट बैंक का प्रमुख काम भुगतान सेवाएं प्रदान करना है। ये बैंक अधिकतम 1 लाख रुपये तक के जमा ले सकेंगे, परंतु इन्हें ऋण प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। इन बैंकों को डेबिट एवं इंटरनेट बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने की छूट होगी, लेकिन क्रेडिट जारी नहीं कर सकेंगे। इन बैंकों के लिए प्राप्त आवेदनों की छंटनी का काम नविकेत मोर समिति ने किया था।

नभ निर्माण

एक नवीन पहल 'नभ (NABH: Nextgen Airports For Bharat) निर्माण' के तहत प्रतिवर्ष एक बिलियन आवकजाही को नियंत्रित करने के लिए हवाई अड्डा क्षमता में पाँच गुना विस्तार करने का प्रस्ताव बजट 2019-20 में दिया गया था। सरकार नभ निर्माण पहल के एक हिस्से के रूप में हवाई अड्डों की क्षमता के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। यात्री सुविधा को बेहतर बनाने, कार्गो संचालन सुविधाओं को बढ़ावा देने एवं उड़ान योजना के तहत 56 नए हवाई अड्डों का आरंभिक परिचालन उनका फोकस क्षेत्र होगा।